गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

BPRD

First-time Offenders

गृह मंत्रालय
MINISTRY OF
HOME AFFAIRS

BPRD

पहली बार के अपराधी

♦ Empathy for first-time Offenders: Justice with Compassion

- Both Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita (BNSS) and Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) 2023 introduce a paradigm shift in the treatment of first-time offenders, emphasising rehabilitation and compassion in the pursuit of justice. In BNSS, reduced minimum punishment in plea-bargaining for first-time offenders and liberalised and relaxed bail for first time undertrials acknowledges that mistakes can be learning opportunities, especially for those entering the justice system for the first time. The legal framework under BNS aims to balance accountability with an empathetic approach towards individuals with no prior criminal history, for instance 'petty theft' which is made punishable with community service.

♦ Rehabilitation over Retribution

- The new laws aim to provide first-time offenders with alternatives to punitive measures, thereby focusing on

पहली बार के अपराधी के प्रति तरसः करुणा के साथ न्याय

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 कानून में पहली बार के अपराधियों के बारे में बदलाव किया गया है, जिसमें न्याय के लिए पुनर्वास और करुणा पर जोर दिया गया है। बीएनएसएस में पहली बार के अपराधियों के लिए न्यूनतम सजा कम की गई और पहली बार के विचाराधीन कैदियों के लिए उदार जमानत स्वीकार की गई है कि जिसमें गलतियां को सुधारने का अवसर दिया गया है। छोटी चोरी जैसे छोटे अपराधों के लिए बीएनएस 2023 के तहत बिना किसी पूर्व आपराधिक इतिहास वाले व्यक्तियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखा गया है, जिसके तहत दंड के रूप में सामूदायिक सेवा करवाया जाएगा।

प्रतिशोध के बदले पुनर्वास

- नए कानूनों का लक्ष्य पहली बार अपराध करने वालों को दंडात्मक उपायों के विकल्प प्रदान करना है जिसमें पुनर्वास और समाज में पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करना है।
- नए आपराधिक कानून एक ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जहां छिटपुट गलतियों को सकारात्मक बदलाव के अवसर के रूप में पहचाना जाएगा।

rehabilitation and reintegration into society.

- The new criminal laws envision a future where isolated mistakes are recognised as opportunities for positive change.

♦ Provisions for First-Time Offenders: A Legal Milestone

Multiple considerations have been introduced through several sections for first-time offenders including:

- Introducing non-custodial punishment such as community service, and counselling for eligible individuals, fostering personal growth and societal reintegration through the legal framework.
- First-time offenders are to be given relaxed punishment (one-fourth and one-sixth of stipulated punishment) in plea bargaining.
- First time under-trial offender is given statutory bail after completion of one-third period of the maximum punishment prescribed.

पहली बार के अपराधियों के लिए प्रावधान: एक कानूनी मील का पत्थर

पहली बार के अपराधियों के लिए कई धाराओं के माध्यम से कई विचार पेश किए गए हैं, जिनमें शामिल हैं :

- सामुदायिक सेवा और परामर्श जैसी सजाओं का प्रावधान किया गया है जिसमें ऐसे अपराधियों को जेल न भेजा जाए और कानूनी प्रावधान के तहत व्यक्तिगत विकास और सामाजिक पुर्नएकीकरण को बढ़ावा देना।
- पहली बार अपराध करने वालों को प्ली बार्गेनिंग में कम सजा (ऐसी सजा का एक-चौथाई और छठा हिस्सा) दी जाएगी।
- पहली बार विचाराधीन कैदी को निर्धारित अधिकतम सजा की एक तिहाई अवधि पूरी होने के बाद जमानत देने का प्रावधान।